www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 31 मार्च 2019

दैनिक जागरण

मानसिक अस्थिरता में आध्यात्मिकता औषधि का काम करती है

आर्थिक सेहत बिगाड़ने वाली योजना

संजय गुप्त

न्यूनतम आय योजना का एलान करने वाली कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं कि क्या सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी या फिर सभी समर्थ लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा?

आम चुनाव के लिए मतदान की तिथियां जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, जनता को रिझाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं कि राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक-लुभावन वादे करेंगे तो फिर जनता में भ्रम ही फैलेगा। अपने देश में बहुत कम मतदाता चुनावी वादों की गहन परख कर पाते हैं। इसी कारण तमाम मतदाता लोक-लुभावन घोषणाओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों को एक निश्चित न्यूनतम आय देने की अपनी योजना का एलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। उनके हिसाब से ऐसे अति गरीब परिवारों की संख्या पांच करोड़ है और प्रत्येक परिवार के पांच सदस्य जोड़ लिए जाएं तो इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या 25 करोड़ होगी। इस योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप हैरान रह गए होंगे। पत्रकारों का तो पता नहीं, लेकिन तमाम अर्थशास्त्री और देश की वित्तीय सेहत की जानकारी रखने वाले इस पर जरूर हैरान रह गए होंगे। इससे इन्कार नहीं कि देश में गरीबों की अच्छी-खासी संख्या है और उन्हें सरकारी मदद की भी जरूरत है, लेकिन आखिर पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने के लिए हर साल तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये का प्रबंध कहां से होगा? क्या सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी या फिर आर्थिक रूप से सभी समर्थ लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं कि इसकी गणना कैसे की जाएगी कि किसी परिवार की मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है?

राहुल गांधी की मानें तो इसका आकलन कर लिया गया है कि न्यूनतम आय योजना को कैसे संचालित करना है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। जब इस योजना को लेकर सवाल उठे तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से अन्य तरह की सब्सिडी में कटौती नहीं होगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार देश के पास इतनी क्षमता है कि इस योजना पर अमल किया जा सके और जानकारों का एक समूह इस योजना की रूप-रेखा तैयार कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि बगैर रूप-रेखा तैयार किए योजना की घोषणा कर दी गई? सच्चाई जो भी हो, अन्य सब्सिडी में कटौती किए बगैर इस योजना को लागू करने का मतलब है नोट छापकर जनता को बांटना। इस स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, राजकोषीय घाटे में दो प्रतिशत की और वृद्धि हो सकती है। स्पष्ट है कि महंगाई बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घटेगी। इस तरह अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और गरीबों को दी जाने वाली राहत का असर भी कम होगा। अगर इस योजना को जबरन लागू किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के साथ यह भी हो सकता है कि गरीब तबका केवल इस योजना के भरोसे रहकर बैठ जाए और मेहनत करने से तौबा कर ले। यह एक तथ्य है कि मनरेगा लागू होने के बाद कुछ समय तक ऐसा ही देखने को मिला था। देश के कई हिस्सों में खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों की कमी महसूस की गई थी। राहुल गांधी और उनके सहयोगी कुछ भी दावा करें, लगता यही है कि इस योजना पर विचार करते समय अर्थव्यवस्था की सेहत का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बावजूद इससे इन्कार नहीं कि कुछ लोग और खासकर गरीब तबका इस योजना से आकर्षित हो सकता है।

अवधेश राजपूत

निःसंदेह गरीबी देश से दूर होनी चाहिए, लेकिन जरूरत गरीब तबके को आत्मनिर्भर बनाने के ठोस उपाय करने की है, न कि उसे सब्सिडी की बैसाखी पकड़ाने की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक यही किया गया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक गरीबी दूर करने का वादा करती रहीं, लेकिन वह दूर नहीं हुई। इसका कारण वे आर्थिक नीतियां रहीं जिनके चलते देश का आर्थिक विकास बाधित रहा। सुस्त आर्थिक रफ्तार के कारण ही देश की विकास दर का उपहास उड़ाते हुए उसे हिंदू विकास दर कहा जाता था। कम से कम कांग्रेस के मौजूदा नेताओं को तो यह पता होना चाहिए कि गरीबी इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे से नहीं, बल्कि नरसिंह राव सरकार की नई आर्थिक नीतियों से दूर होनी शुरू हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि उसी तर्ज पर उनकी नई योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। अच्छा होता कि वह यह भी बताते कि मनरेगा के तहत जो काम कराए गए उससे कहीं पर भी बुनियादी ढांचे का निर्माण क्यों नहीं हो सका? यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि संप्रग शासन के दौरान मनरेगा के तहत जो राशि गरीबी दूर करने के नाम पर वितरित की गई उससे गरीबी दूर करने में कोई खास सफलता नहीं मिली। मनरेगा लागू होने के बाद यह भी देखने को मिला कि गरीब तबके के एक वर्ग ने कर्मठता का परित्याग कर दिया।

कोई भी देश आर्थिक प्रगति तभी करता है जब उसके नागरिक अपने बलबूते अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल यह है कि कांग्रेस गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं की पैरवी मुश्किल से ही करती है। यह एक सच्चाई है कि वह बार-बार कर्ज माफी जैसी योजनाएं लेकर सामने आती है। वह इससे अपरिचित नहीं कि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होता। उलटे वे बार-बार कर्ज लेने को बाध्य होते हैं। अब तो स्थिति यह है कि चुनाव वाले राज्यों में समर्थ किसान भी कर्ज चुकाने से बचते हैं। क्या गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि इससे समाज में एक नई तरह की असमानता आ सकती है? ध्यान रहे कि इसके अच्छे-खासे आसार हैं कि सभी गरीब इस योजना के दायरे में न आ सकें। इसके अलावा इसकी पहचान भी कठिन ही होगी कि कौन गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है? यह कठिनाई इसलिए और बढ़ेगी, क्योंकि तमाम गरीब ऐसे हैं जिनकी आय कम-ज्यादा होती रहती है? अच्छा होगा कि कांग्रेस इससे अवगत हो कि अगर तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये से स्कूल, अस्पताल बनें और कानून एवं व्यवस्था का तंत्र मजबूत किया जाए तो उससे गरीबों को कहीं अधिक लाभ मिलेगा।

राजनीतिक दल जिस तरह आर्थिक स्थिति की अनदेखी करके लोक-लुभावन वादे करने लगे हैं उसे देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे उन्हें बेलगाम घोषणाएं करने से रोका जा सके। बेहतर हो कि चुनाव आयोग को यह अधिकार मिले कि वह राजनीतिक दलों के चुनावी वादों की परख करे और उनके नफा-नुकसान से जनता को अवगत कराए। आज भले ही कांग्रेस न्यूनतम आय योजना को बाजी पलटने वाली मान रही हो, लेकिन सच यह है कि इस तरह की योजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

response@jagran.com

पुरानी व्यवस्था की बहाली

बीते कुछ समय से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक बड़े-बड़े एलान करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने घोषणा की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नीति आयोग को खत्म कर दिया जाएगा। इसके पहले वह जीएसटी में भी बड़े बदलाव की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा यह भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम आय की योजना लागू की जाएगी। जैसे इस योजना को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका एलान करने के पहले आवश्यक विचार-विमर्श किया गया उसी तरह इस पर भी सवाल खड़े हों तो हैरानी नहीं कि आखिर नीति आयोग को खत्म करने की घोषणा किस आधार पर की जा रही है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि नीति आयोग को खत्म करके फिर से योजना आयोग का निर्माण करने से क्या हासिल होगा? यह ठीक है कि राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया कि भावी योजना आयोग में जाने-माने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को रखा जाएगा और इन अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के साथ कुल स्टाफ की संख्या सौ से कम होगी, लेकिन क्या वह यह कहना चाह रहे हैं कि नीति आयोग में ऐसे लोगों की कमी है? निःसंदेह यह भी समझना कठिन है कि सौ से कम संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या पहले वाला योजना आयोग इसीलिए अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा कि उसमें स्टाफ की संख्या सौ से कम नहीं थी? पता नहीं राहुल गांधी क्या कहना और करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि संस्थाओं को सक्षम बनाने वाले विचार सामने रखें जाएं और उनमें फेरबदल करने की जरूरत के पीछे ठोस कारण गिनाए जाएं। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ करने के बजाय सिर्फ एक ट्वीट कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी।

इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी ने योजना आयोग की जगह बने नीति आयोग को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें यह भी स्मरण होना चाहिए कि एक समय राजीव गांधी ने भी योजना आयोग के कामकाज से नाखुशी जताते हुए कहा था कि आखिर यह करता क्या है? राहुल गांधी को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मनमोहन सरकार के समय योजना आयोग को निष्प्रभावी करने का काम एक बड़ी हद तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने किया था। यह संभव है कि नीति आयोग राहुल गांधी के मन मुताबिक काम न कर रहा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे खत्म करके वह पुरानी व्यवस्था बहाल करने का वादा किया जाए जिसके बारे में आम धारणा यही थी कि वह अप्रासंगिक हो चुकी है। बेहतर होता कि राहुल गांधी ऐसा कोई विचार सामने रखते जिससे नीति आयोग को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने में मदद मिलती। योजना आयोग फिर से बनाने की उनकी घोषणा से तो यही लगता है कि वह हर पुरानी व्यवस्था को बहाल करना बेहतर समझ रहे हैं। ध्यान रहे कि उन्होंने अपनी न्यूनतम आय योजना को मनरेगा-2 का नाम दिया है।

एनआरसी पर बहस

चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का मुद्दा गरमाने लगा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा उत्तर बंगाल के अलीपुरदुआर से चुनाव प्रचार शुरू करने के दौरान सभी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की बात कहने से एक बार फिर यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। शाह ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी और पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी लागू किया जाएगा। राज्य से सभी घुसपैठिये निकाल बाहर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घुसपैठिये तृणमूल कांग्रेस के आधार हैं। उनके निकाल बाहर करने पर बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक जड़ें उखड़ जाएंगी। शाह ने हिंदू शरणार्थियों को सम्मान के साथ भारत में रहने की व्यवस्था करने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी महासचिव व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी नहीं लागू करने दिया जाएगा। नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने और दो कदम आगे बढ़कर कहा है कि अमित शाह एनआरसी लागू करने की बात कहेंगे तो यहां की जनता उन्हें फिर कभी राज्य में घुसने नहीं देगी। एनआरसी पर दोनों पक्ष आक्रामक है। इसके मूल में राजनीतिक कारण है। भाजपा राष्ट्रीयता पर जोर देती रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और ममता सरकार का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण भाजपा का अहम मुद्दा है। अमित शाह के राज्य से एक-एक घुसपैठिये को निकाल बाहर करने की बात कहने का एक अर्थ यह भी है कि ममता सरकार के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में यह गंभीर समस्या बन गई है। इसी तरह शाह के हिंदू शरणार्थियों की वकालत करने का मतलब भी भाजपा का वोट बैंक मजबूत करना है। असम में एनआरसी से 40 लाख लोगों का नाम कट जाने से उनकी नागरिकता संकट में पड़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरअसी से 40 लाख लोगों के नाम बाहर करने का कड़ा विरोध किया था। लेकिन यहां सभी पक्षों को घुसपैठिये और शरणार्थियों के बीच अंतर को समझना होगा और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना होगा। इस तरह की गंभीर समस्याओं को चुनावी नफा नुकसान से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए।

चुनावी पहेली सुलझाने की होड़

साकेत सूर्येश

सावन में प्रकट होने वाले मेंढकों की भांति बैनर, पोस्टर वालों के साथ चुनाव विश्लेषकों की नई खेप चैनलों पर उतर आई है

चुनावी घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई। सब कुछ जस का तस थम गया है। प्रेमिका की आती हुई स्वीकृति अब मई की प्रतीक्षा में है। पाजामा थामे हुए प्रेमी मेघदूतम के यक्ष की भांति चुनावी नारों के माध्यम से प्रियतमा तक संदेश भेजने पर विचार कर रहा है, किंतु चुनाव संबंधी आचार संहिता को लेकर असमंजस में है। इस चुनावी दौर में सोशल मीडिया पर पांचजन्य के उद्घोष के साथ ट्विटर-वीरों ने धनुष संधान कर लिए हैं, कीबोर्ड-रूपी गांडीव धारण किए युवा पार्थ उत्साहपूर्वक युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं। महारथी टैग-रूपी शब्दबाण छोड़ते हैं जो धनुष की टंकार के मध्य अनगिनत हैशटैगों का रूप धारण करके आकाश को आच्छादित कर देते हैं।

युद्धक्षेत्र एक सेना से दूसरी सेना की ओर आते-जाते महारथियों के पदचापों से गुंजायमान है। महान वीर ध्वजों का आदान-प्रदान कर रहे हैं। कुछ योद्धा अपनी छोटी-छोटी युद्धभूमि बनाकर उसी में लड़ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ के प्रतापी सम्राट महायुद्ध की अक्षौहिणी सेनाओं के मध्य अपनी टिटिहरी सेना लिए हुए उतरे हैं और युद्ध क्षेत्र के योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अधेड़ होता अभिनेता मुष्टिकाएं भींच, मांसपेशियां अकड़ा कर एक्शन सिनेमा के निर्माता को लुभाने का प्रयास करता है। सैनिक वेशभूषा-धारी रिंकिया के पापा रथ लेकर पाकिस्तान सीमा की ओर प्रस्थान करने को आतुर दिखते हैं। दिल्ली सल्तनत इस चुनावी संग्राम में ओखला से बदरपुर के मध्य सीमित होती जान पड़ती है। दिल्ली के आधे-अधूरे सुल्तान इसी ऊहापोह में हैं कि धरना करना है या नहीं करना है और अगर धरना नहीं करना है तो क्या करना है। यह चुनाव पाठ्यक्रम से बाहर जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने आप से गठबंधन को लगभग मना कर दिया है और विधि का विधान या ऊपर वाले का बेआवाज लट्ठ देखिए कि यूपी में बहनजी ने भी कांग्रेस के हाथ को लगभग गुस्से से ही झटक दिया है।

कांग्रेसी खेमे में अपनी ही चिंताएं हैं। राजकुमार अपने घातक अस्त्रों को पिछले चुनावों मे उपयोग करके श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। मंदिरों में टहलने के बाद युवराज के पास फैंसीड्रेस के विकल्प समाप्तप्राय हैं। तरकश के राफेल इत्यादि तीर रामानंद सागर के धारावाहिक के शस्त्रों की भांति जगमगाकर धराशायी हो चुके हैं। युवराज्ञी की नाक की नानी से समानता का प्रारंभिक उत्साह भी अब बोर करने लगा है। जैसे संध्या होते ही बछड़े माता के पास लौट आते है, चुनावी संध्या में भीम आर्मी के विकट वीर और हार्दिक पटेल जैसे महान योद्धा कांग्रेस की गौशाला की ओर लौट रहे हैं, लेकिन अदालत उनके अरमानों पर पानी फेर रही है। सपा 'पार्टी ही परिवार है' और 'परिवार ही पार्टी है' के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ने पर आमादा है।

पार्टी प्रवक्ताओं ने अपनी कुर्सियों के पीछे मोटी-मोटी किताबें जमा ली हैं। जिनके पास किताबें नहीं हैं, उन्होंने पुस्तक की फोटो वाले वॉलपेपर लगवा लिए हैं। प्रवक्ता सीरीज के वॉलपेपर की मार्केट में पुस्तकों और साक्षात प्रवक्ता से अधिक डिमांड है। चैनलों का माहौल देखते हुए सत्तर के दशक के बूथ कैप्चरिंग वाले बलिष्ठ पहलवान आज वॉलपेपर लगाकर प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। सावन में प्रकट होने वाले मेंढकों की भांति बैनर, पोस्टर वालों के साथ चुनाव विश्लेषकों की नई खेप टीवी चैनलों पर उतर आई है। किस्म-किस्म के सेफोलॉजिस्ट गरारे करके वाणी की सौम्यता का अभ्यास कर रहे हैं।

एक दिशा से जहां 'चौकीदार चोर है' का उद्घोष होता है वहीं दूसरी दिशा 'मैं भी चौकीदार' का जयघोष दूसरे खेमे से उठकर उसे डुबा देता है। इस सबके बीच चुनाव आयोग मंद स्वर में जनता के बीच 'जागते रहो' पुकारता हुआ लाठी खटका रहा है। जनता ऊंघ सी रही है और चुनावी घोषणा पत्रों की प्रतीक्षा में कलर टीवी और लैपटॉप की खरीददारी रोके बैठी है। हमारे पड़ोस के छगनलाल जी ने दाढ़ी बनाना भी इस उम्मीद के साथ बंद कर दिया है कि उनकी दाढ़ी चुनाव तक प्रत्याशी ही बनवाएंगे और उनका मत उसी प्रतिभाशाली प्रत्याशी के पक्ष मे गिरेगा जो शेव के साथ पैडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल वगैरह करा के देगा। नोटावीरों ने चुनाव की तारीखों का संज्ञान लेते हुए, लांग वीकेंड की व्यवस्था कर ली है। मुफ्त वाईफाई वाले होटल ढूंढ लिए गए हैं ताकि वहां से भारत के राजनीतिक और नैतिक पतन पर ब्लॉग निर्बाध रूप से लिखे जाएं। राग दरबारी और कैंब्रिज एनालिटिका आपस मे संघर्षरत हैं और श्रीलाल जी के शिवपालगंज में चुनाव आयोग की लाठी की खटखटाहट सुन कर वैद्यजी पूछते हैं, यह कैसा कुकुरहाव है और लाठी को तेल चढ़ाते तृणमूल कांग्रेस के बदरी पहलवान उत्तर देते हैं, देश में चुनाव है।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | भारतीयों की चिंता के विषय

(23 मई-23 जुलाई 2018 के बीच किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष)

स्रोत : प्यू रिसर्च सेंटर

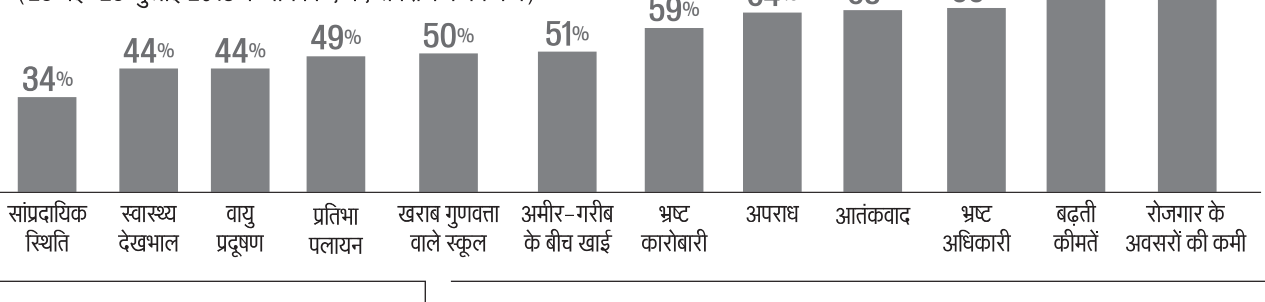

ऊर्जा

व्यवहार

हंस और बगुला लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। उनमें अंतर करना कठिन होता है। इससे कोई भी भ्रमित हो सकता है, लेकिन उनकी पहचान उनके व्यवहार से होती है। हंस केवल मोती चुगता है और इसी से उसकी पहचान बनती है। बगुले की वास्तविकता तब स्वतः प्रकट हो जाती है जब वह अपनी चोंच में कुछ भी धारण कर लेता है। संसार भी इसी प्रवृत्ति के दो तरह के मनुष्यों से भरा है। पदार्थवाद और भौतिकवादी सोच ने सभी को दिखावे के भंवर में समेट लिया है। मनुष्य को जानना और पहचानना कठिन हो गया है। धर्म जगत में यह चुनौती आरंभ से ही विद्यमान है। आडंबर अध्यात्म का रूप धारण कर छल रहा है। धर्म के नाम पर पाखंड का सिलसिला जारी है। अध्यात्म महापुरुषों और प्रभु कृपा की सौगात है, जबकि आडंबर का संबंध धर्म के नाम पर कर्मकांडों का प्रदर्शन करना है। मनुष्य के वैयक्तिक स्वार्थ उसे पाखंड की ओर इसलिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि पाखंड का आधार आदान-प्रदान और त्वरित प्रक्रिया है। ये क्षणिक सांत्वना तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु अंततः निष्फल होते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं, जो धर्म-स्थलों पर श्रद्धालु हो जाते हैं, किंतु समाज और परिवार में आते ही बगुले की तरह अपनी चोंच में कुछ भी रखने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग धर्म-स्थलों पर श्रद्धा की भावना में बह जाते हैं और फिर वहां से निकलकर स्वार्थ की दुनिया में एक बार फिर कैद हो जाते हैं।

महापुरुषों ने हंस के गुणों पर अमल करने की राह दिखाई है। मनुष्य प्रेम, विनम्रता, परोपकार, समदृष्टि और करुणा के मोती चुनें और इसे अपनी वृत्ति बना ले। इन गुणों को पाने के लिए हंस जैसा धैर्य होना चाहिए। हंस मोती की पहचान स्वयं करता है और उसके पास आने पर ही अपनी चोंच खोलता है। मनुष्य भी महापुरुषों की शिक्षाओं से सीख लेकर धर्म-अध्यात्म की पहचान करे। हंस को कहीं यह सिद्ध करने के लिए जाना नहीं पड़ता कि वह हंस है। उसकी चोंच में चूंकि मोती ही स्थान पाता है, जिससे यह प्रमाणित होता जाता है कि वह हंस है। बगुला दिखने में एकदम हंस जैसा लगता है, किंतु उसकी चोंच में आने वाली मछलियां व अन्य जल-जंतु सिद्ध कर देते है कि वह हंस नहीं है। धर्म और अध्यात्म एक वृत्ति है, जो मनुष्य के जीवन को संपूर्णता में प्रभावित और परिवर्तित करती है।

डॉ. सत्येंद्रपाल सिंह

जलवायु परिवर्तन के नए खतरे

मुकुल व्यास

प्रतिकूल मौसम की मार से कई फसलों पर ऐसा दुष्प्रभाव पड़ सकता है कि पोषण के बजाय बीमारियों को आमंत्रण देने लगें

ग्लोबल वार्मिंग कई तरह से पृथ्वी को प्रभावित कर रही है। अब एक नई बात यह सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन से गरीब देशों में रहने वाले लोगों की खाद्य आपूर्ति विषाक्त हो सकती है, क्योंकि तापमान वृद्धि से निपटने के लिए फसलों को विषैले रसायन उत्पन्न करने पड़ते हैं। महत्वपूर्ण फसलों पर प्रतिकूल मौसम के विनाशकारी प्रभावों के बारे में काफी अध्ययन हो चुका है। विषम मौसम से फसलों पर कुछ और भी प्रभाव पड़ते हैं जिनके बारे में अभी तक अधिक जानकारी नहीं थी। सूखा पड़ने पर मक्का, बीन्स और केसावा जैसे पौधे अधिक मात्रा में नाइट्रेट और हाइड्रोजन सायनाइड उत्पन्न करते हैं।

ये रसायन मवेशियों और मनुष्यों, दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। गर्म मौसम में टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले फंगल इन्फेक्शन फैलने से नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अफ्रीका में हर साल लीवर कैंसर के हजारों मामले सामने आते हैं। इन मामलों के लिए फंगल इन्फेक्शन को जिम्मेदार माना जाता है। तापमान बढ़ने पर दुनिया के उत्तरी हिस्सों में भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक जैकलीन मैकग्लेड ने हाल में फसलों पर तापमान वृद्धि के प्रभावों को रेखांकित किया। इसमें प्रो. मैकग्लेड की रुचि उस समय उत्पन्न हुई जब इथियोपिया से गरीब किसानों और उनके मवेशियों की रहस्यपूर्ण मौतों की खबरें आईं। इन समस्याओं के कारण लोगों में दृष्टिहीनता और चलने-फिरने में दिक्कत जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं और उन्हें जान भी गंवानी पड़ी। सूखे से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं जिसकी वजह से उन्हें सड़कों के किनारे उगने वाले जंगली पौधे खाने के लिए विवश होना पड़ा। दुर्भाग्यवश सूखे ने इन पौधों के अंदर रक्षा प्रणाली को भी सक्रिय कर दिया जिससे उनमें अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन सायनाइड उत्पन्न हो गया।

प्रो. मैकग्लेड ने इस विषय पर सारी सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में समाहित किया। इसमें उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में नई पर्यावरणीय समस्याएं पहचानीं। प्रो. मैकग्लेड ने कहा कि उन्होंने इन मुद्दों को भविष्य में खतरे की घंटी समझ कर उठाने की कोशिश की थी। बड़ी समस्या बनने से पहले लोगों को इसके बारे में सचेत करना आवश्यक था। यह जरूरी है कि हम इन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक गौर करें, क्योंकि इनका सीधा संबंध हमारी खाद्य सुरक्षा से है। जिन पौधों पर हमारी निर्भरता है वे ही जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढालने लगे हैं।

उनका यह तरीका मनुष्यों और मवेशियों के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रो. मैकग्लेड की रिपोर्ट के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल के अधिकांश अध्ययनों ने प्रतिकूल मौसम और खाद्य प्रणालियों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर गौर किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रभाव अभी से महसूस किए जाने लगे हैं। पिछले साल कैलिफोर्निया से लेकर स्वीडन तक भीषण गर्मी और सूखे का प्रभाव पड़ा। ये समस्याएं एफ्लाटॉक्सिन जैसे रसायनों से उग्र हो सकती है। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला रसायन है जो सूखे की स्थितियों में मक्के और अन्य फसलों पर उगने वाली फफूंदी द्वारा उत्पन्न किया जाता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

गजब की बेचैनी

चुनावी दंगल में वैसे तो नेताजी इससे पहले भी ताल ठोक चुके हैं, लेकिन इस बार वह अखाड़े में उतरने के बाद कुछ बेचैन से हैं। वजह कुछ और नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है जिसके चलते अब उन्हें अपने आपराधिक रिकॉर्ड को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रकाशित करवाना पड़ेगा। यह भी कोई ऐसे वैसे अखबार या टीवी चैनल में नहीं, बल्कि चुनाव आयोग जिसमें कहेगा, उनमें छपवाना होगा। दरअसल ऐसे नेताओं की काफी संख्या है जो लगातार राजनीति में रहते हुए सिर्फ दबंग नेता की छवि बनाए हुए हैं, लेकिन उनके आपराधिक रिकॉर्ड को लोग भूल चुके हैं। अब फिर से अखबारों में छपवाकर लोगों के जेहन में उसे जिंदा करना होगा। यह कदम खुद अपने ऊपर ही खंजर चलाने जैसे होगा। अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले सरकार के एक जूनियर मंत्री जी अपने किसी एक पुराने मामले को लेकर परेशान हैं। फिलहाल वह इसे लेकर कानूनी राय लेने में जुटे हुए हैं।

तुरुप का पत्ता

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से समीकरण बिगाड़ तृणमूल छोड़कर आए मुकुल राय भाजपा के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं। कभी ममता के राइट हैंड मैन माने जाने वाले मुकुल ने पिछले दिनों में न सिर्फ अलग-अलग दलों से तोड़कर नेताओं को भाजपा से जोड़ा है, बल्कि अब कागजी तैयारी में भी जुटे हैं। बताते हैं कि चुनाव मे अर्द्धसैनिक बलों के इस्तेमाल को लेकर भी आधार तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर स्थानीय पुलिस को बूथ से दूर रखने की सलाह दी है। ममता इसके खिलाफ हैं, लेकिन यही ममता थीं जिन्होंने वाम सरकार के दौर में वहां सेना के निरीक्षण में चुनाव करवाने की बात की थी। यह बताने की जरूरत नहीं कि उस वक्त यह चिट्ठी लिखी किसने होगी।

जाएं तो जाएं कहां..

कीर्ति आजाद के क्रिकेट का सबसे हाई प्वाइंट था जब उन्होंने पाकिस्तान के मध्यम तेज गेंदबाज जलालुद्दीन की गेंदों पर लगातार तीन छक्के मारे थे। राजनीति में उनका अभी तक सबसे बड़ा मुकाम यही रहा है कि वह दो दफा दरभंगा से विजयी हो कर लोकसभा पहुंच चुके हैं। तीसरी दफा उनके लोकसभा पहुंचने को लेकर तमाम किंतु-परंतु लग चुके हैं। एक तो उनकी पसंद की दरभंगा सीट ही उन्हें नहीं मिल पाई है और बाल्मिकी नगर की जो सीट उन्हें दी जा रही है वह उनके लिए एकदम नई है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद भी आजाद भारतीय क्रिकेट में कोई खास जगह नहीं बना पाए वैसा इस बार उनके साथ राजनीतिक मंच पर भी न हो।

साहब गदगद हैं

कहतें हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। नीति आयोग के एक पदाधिकारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साहब को मीडिया में दिखने की बड़ी हसरत रहती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह सुर्खियों में जगह बनाने में नाकाम रहे थे। कई बार उन्होंने पत्रकारों को बुलाकर ऊबाऊ तकनीकी विषयों पर ज्ञान दिया, लेकिन मनवांछित फल नहीं मिला। आखिरकार पिछले हफ्ते ऐसी घटना हुई जिससे उनकी बाछें खिल गईं। दरअसल प्रधानमंत्री ने जब मिशन शक्ति के सफल परीक्षण का एलान किया तो मीडिया इन महोदय के पास पहुंच गया। उनके स्टाफ को समझ ही नहीं आया कि मीडिया को कैसे संभालें। वह पूरे दिन कैमरे पर चहकते हुए नजर आए। बताया जाता है कि अचानक प्रचार पाने के बाद साहब गदगद हैं। उधर उनके आस-पास बैठने वाले बाबू कह रहें कि इस बार तो साहब ने ऊंची पतंग उड़ा दी। अब देखना यही होगा कि साहब को अगली दफा ऐसा मौका कब मिलेगा।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।